RSS-HMS/4B/6.00

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : ये जनता से इतने कटे हुए हैं कि पहली बार ..(व्यवधान).. हमें संतोष होना चाहिए, आम तौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार by and large आमने-सामने होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ..(व्यवधान).. यह पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे, लेकिन सरकार और जनता साथ-साथ थी। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए ..(व्यवधान).. हो सकता है, आपकी कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा और विश्व के सामने हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के सवा सौ करोड़ लोग ऐसे हैं, वे अनपढ़ हो सकते हैं, उन्हें शायद शिक्षा न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन कर रहे थे और जो रिपोर्ट कार्ड आप दे रहे थे कि ऐसा है, वह सब होते हुए भी यह देश है जो अपने भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई भी दल हो, यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं, जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने को तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। इसलिए हमें भी इस बात को समझना होगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : ये सब आपकी बुराइयां भुगत रहे हैं, जब से आपकी सरकार आयी है ..(व्यवधान)..

शहरी विकास मंत्री (श्री एम0 वेंकैया नायडु) : सर, यह क्या है?

श्री नरेन्द्र मोदी : हम यह भी जानते हैं ..

श्री एम0 वेंकैया नायडु : सर, एक मिनट। सॉरी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ..(व्यवधान) Is the running commentary allowed in the House? मर्यादा है? संस्कार होने चाहिए। ..(व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र मोदी : सभापति महोदय जी ..(व्यवधान)..

श्री रेणुका चौधरी : डा0 मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपने बहुत संस्कार दिखाए ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Silence please.

श्री नरेन्द्र मोदी : आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है, हम तो ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please sit down...(Interruptions)...

श्री नरेन्द्र मोदी : पिछले सत्र में डा0 मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। यह बात सही है कि अभी शायद आपकी तरफ से एक किताब निकली है। उसका foreword डाक्टर साहब ने लिखा है। मैं जब आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला कि किताब किसी और ने लिखी, foreword उन्होंने लिखा है। ..(व्यवधान).. तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा कि शायद ..(व्यवधान).. यह बात बड़ी समझने की है कि पिछले करीब-करीब 30-35 साल से ..(व्यवधान)..

श्री आनन्द शर्मा : आप प्रधान मंत्री हैं, पूर्व प्रधान मंत्री के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वे आप से ज्यादा इकोनॉमी जानते हैं। ..(व्यवधान)... It is a breach of privilege... (Interruptions)... On this, we will not. How can he...(Interruptions)...

श्री सभापति : शर्मा जी, बैठ जाइए।

श्री नरेन्द्र मोदी : करीब-करीब 30-35 साल से ..(व्यवधान).. जो शब्द मैं बोला भी नहीं, वह समझ गए।

MR. CHAIRMAN : Why are you interrupting? Please sit down.(Interruptions)…

श्री नरेन्द्र मोदी : जो शब्द में बोला भी नहीं, उसका अर्थ समझ गए, यह बड़ी गज़ब की बात है। डा0 मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल से भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा है ..(व्यवधान).. और निर्णायक भूमिका में रहा है। इस देश में अर्थ-जगत का शायद ही कोई ऐसा अकेला व्यक्ति होगा, जिसका हिंदुस्तान की 70 साल की आजादी में आधे समय इतना दबदबा रहा होगा।

(4 सी/एएससी पर जारी)

ASC-KGG/ 4C/6.05

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खासकर के हम राजनेताओं के लिए...(व्यवधान). ... डा. साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है, इतना सारा हुआ और उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेन-कोट पहनकर नहाना, इस कला को तो डा. साहब ही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता है। ....(व्यवधान)... इसलिए ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Order in the House, please. ...(Interruptions)... Please sit down. Everyone should go back to their places. ...(Interruptions)...You can't do this. All of you should sit down. ...(Interruptions)... Everyone, go

back to your places. …(Interruptions)… Go back to your places. …(Interruptions)… आप बैठ जाइए। ….(व्यवधान)…आप लोग वापस अपनी जगह पर जाइए। ….(व्यवधान)…Please go back. …(Interruptions).. Please go back. …(Interruptions)… I am appealing to hon. Members to sit down. …(Interruptions)…

SHRI ANAND SHARMA: The Prime Minister is provoking, Sir. …(Interruptions)… He is casting aspersions. …(Interruptions)…

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) : हम भी हाउस के मेम्बर हैं। ….(व्यवधान)… हमने सब सुना है। ….(व्यवधान)…

श्री आनन्द शर्मा: ये कहते हैं स्कैम ….(व्यवधान)… इसकी जांच होनी चाहिए। ….(व्यवधान)…

MR. CHAIRMAN: This is not fair. You can't do this, please. …(Interruptions)… आप बैठ जाइए। …(व्यवधान)….आप लोग वापस अपनी जगह पर जाइए। …(व्यवधान)…

SHRI ANAND SHARMA: In protest, we are walking out, Sir. …(Interruptions)…

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

MR. CHAIRMAN: Please go back to your places. …(Interruptions)…

विधि और न्याय मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : आप अपनी बात कहकर सुनना नहीं चाहते हैं। ….(व्यवधान)… आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। ….(व्यवधान)… आपको

सच्चाई बार-बार सुननी पड़ेगी। ....(व्यवधान)... आप सच्चाई सुनने से भाग रहे हैं! ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I appeal to hon. Members to sit down. ...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : आप बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं। सर, ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। ....(व्यवधान)... ये हमेशा सच्चाई सुनकर भागते हैं। ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(Interruptions)...

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : ये सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? ....(व्यवधान)...इतनी गंदी बातें कही गईं, हमारे प्रधान मंत्री के बारे में । ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please maintain the decorum in the House. ...(Interruptions)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : हम लोग चुप रहे। ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप लोग क्या कर रहे हैं? ....(व्यवधान)...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, I request you to go through the records. The Prime Minister was called a Hitler. The Prime Minister was called a Mussolini.

The Prime Minister was called a...

MR. CHAIRMAN: Which record are you referring to?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It has happened in the House. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: If approached, action could have been taken. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The same party.…(Interruptions)…

आप हमको सिखाइए मत।....(व्यवधान)…

They are saying this inside the House and outside the House too. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Please, वेंकैया जी, बैठ जाइए। …(व्यवधान)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am very sorry to say this, Sir. The Chair should keep in mind the sentiments of all sides of the House. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Are you suggesting that it is not? …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not saying that. The Chair should understand our pains. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: I understand everybody's pains. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Prime Minister, who has been elected, is appreciated by the entire world. But, these people don't allow the Prime Minister to speak. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down, Venkaiahji? …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: These people participate and say anything. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Everybody should sit down. …(Interruptions)… Now, go back to your places. Just go back to your places. Everybody, sit down. …(Interruptions)… Please…(Interruptions)… That is enough.

MR. CHAIRMAN: Everyone should please sit down. …(Interruptions).. Hon. Prime Minister, please.

(Followed by KLS/4D)

LP-KLS/6.10/4d

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब "लूट" और "प्लंडर" जैसे शब्द प्रयोग किए थे, तब पचास बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि जब मर्यादा इधर लाँघते हैं, तो सुनने की भी तैयारी करें। हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं और यह हम संविधान की मर्यादाओं में रहकर करते हैं। हम लोकतंत्र का आदर करते हुए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार नहीं करना, यह कब तक चलेगा?

आदरणीय सभापति जी, यह बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे और आज हम देश में देखते हैं कि कहीं एक छोटा-सा, कुछ अकस्मात ही प्रकरण हो जाए, तो भी दो-चार गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, कहीं बस भी लेट आ जाए, तो भी एकाध, दो बसें जला दी जाती हैं। इसके बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे, वह तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोज़मर्रा की घटनाएँ हैं। हमारे

भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने ऐसी कोई घटना होने नहीं दी। हमें पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों की इस सामर्थ्य को गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तभी जाकर इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार से सोचते हैं।

मैं आज एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मसला ऐसा था - हमारी और सीताराम येचुरी जी की विचारधारा अलग है, इसलिए विचारों की प्रस्तुति अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक ऐसा विषय था - जब मैं सोच रहा था, तो मुझे इसकी पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल इस काम में हमारे साथ रहेगा। उसका कारण था। उसका कारण यह था कि आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु थे। उन्होंने 1972 में, वांचू कमेटी की रिपोर्ट हाउस में रखने की बड़ी माँग की थी और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी, आखिरकार वे एक कॉपी ले आए और उन्होंने खुद ही टेबल पर रखी। उन्होंने खुद ही, ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को प्राइवेट मेम्बर के नाते टेबल पर रखा। उस दिन उनका जो भाषण हुआ था, वह आज भी प्रासंगिक होता है। उन्होंने 26 अगस्त, 1972 को कहा था, "सर, 12 नवंबर, 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारिशों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गाँधी काले धन के दम पर ही बची हुई हैं। उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है, इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि डेढ़ साल तक

दबाये भी रखा गया।" यह ज्योतिर्मय ज्यार्तिमय बसु जी ने 26, अगस्त, 1972 में कहा था। ..(व्यवधान)..दुबारा ..(व्यवधान)..

श्री सीताराम येचुरी : आपने यह बात उठाई है, तो मैं कुछ कहूँ?

श्री नरेन्द्र मोदी: दोबारा, 4 सितंबर, 1972 को लोक सभा में भाषण देते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, "मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए..।

(KLG/4E पर जारी)

KLG-SSS/4E/6.15

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत): लेकिन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार का चरित्र है, एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। यह मैं 1972 की बात कर रहा हूँ।

श्री सीताराम येचुरी: सर, आप जो यह कह रहे हैं, तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेन्द्र मोदी: और यह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने 4 सितंबर, 1972 को कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त, 1981 को इसी सदन में भाषण दिया और उसमें उन्होंने पूछा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती है? क्या सौ रुपए के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? यह सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस

लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और आप देंगे, मैं आशा करता हूँ। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन यह काम ऐसा है, जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है।

श्री सीताराम येचुरी: सर, आपने यह सवाल उठाया है, तो एक मिनट बोल लूं?

श्री नरेन्द्र मोदी: अपनी बात आप बाद में कर लेना, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, कहीं न कहीं से आ जाओगे। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: काले धन को रोकने के विरोध में हम कभी नहीं थे और न रहेंगे, सवाल यह है कि तरीका क्या है? आपने जिस तरीके से किया, उससे काला धन खत्म नहीं किया। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Sitaramji, please sit down.

श्री नरेन्द्र मोदी: यह तो समय बताएगा। यह बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसले लेना, आम तौर पर लोग मानते हैं कि पापुलिस्ट कदम लेना यह लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के फैसले करना स्वभाव बन जाता है, इसलिए इतने बड़े फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, धीरे-धीरे लोग समझ जाएंगे। जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा फैसला देश का कितना बड़ा भला करने की संभावनाएं लेकर आया है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

सर, यहां पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। मैं हैरान हूँ, सामने से जितने भाषण हुए, कहा कि इस देश में यह नहीं है, ढिमका नहीं है, फलां नहीं है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, टॉयलेट हैं तो पानी नहीं है, पता नहीं क्या-क्या बोला गया। मैं

सोच रहा था कि ये जो बोल रहे हैं, वे क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि वे हिंदुस्तान की 70 साल की सरकारों का रिकॉर्ड दे रहे थे। जो भी बोल रहे थे, यह नहीं है, तो यह 70 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 70 साल में मेरा कंट्रिब्यूशन ढाई साल का ही है। आपने टॉयलेट बना दिया तो क्या मैंने ताला लगा दिया? आपने रोड बना दी तो क्या मैंने उखाड़ कर फेंक दी? आपने पानी का पाइप डाला था तो क्या मैंने आकर काट दिया? यह हकीकत है। कोई यह नहीं कहता कि हिंदुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है। कौन कहता है? सवाल यह है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली शहर में, संभावना है, चलो दिल्ली से शुरू करो। हम लोग कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। यह बीहेवियर चेन्ज का विषय है। अगर कोलकाता के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कोलकाता में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी है, तो वहीं से शुरू करो। हो सकता है कि दूर-सुदूर बंगलादेश के बॉर्डर पर गांव में नहीं हो। यह कहना और फिर हम इस बात के तो गीत गाते रहते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, ढिमका कर दिया, जब उसको लागू करने की बात आई, तो तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है, हम शब्दों का खेल खेलते हैं। हर कोई मानता है, किसी भी बच्चे को पूछो कि स्कूल डेली जाते हो? किसी को भी, आपकी संतानों को भी पूछूंगा, तो कहेंगे कि हां, डेली जाता हूँ। यह मुझे भी मालूम है, उसे भी मालूम है कि संडे को नहीं जाता है। सब को मालूम है।

(4एफ/एकेजी-एनबीआर पर जारी)

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : यह स्वाभाविक है। उसी प्रकार से देश में cashless का मतलब है धीरे-धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े-बड़े समृद्ध देश चुनाव करते हैं, तो बैलेट पेपर छाप कर, ठप्पे मार कर चुनाव करते हैं। जिस देश को अनपढ़ माना जाता है, वह हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वह बटन दबा कर वोटिंग करता है। जिस दिन बटन दबाने की व्यवस्था आई होगी, किसी ने सोचा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी adopt कर सकता है! यानी हम अपने देश की शक्ति को कम न आँकें। हाँ, अगर हमें लगता है कि यह रास्ता ही गलत है, तब तो ठीक है, लेकिन असुविधा है, तकलीफ है, इसलिए छोड़ देना, यह सही नहीं है। असुविधा होगी, व्यवस्थाएँ कम होंगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या दुनिया में कोई देश है? दुनिया के कई देश, मैं हैरान हूँ, आनन्द शर्मा जी कह रहे थे, आपको आश्चर्य होगा, कोरिया ने डिजिटल पर जाने के लिए जो incentive scheme बनाई है, यह इतनी बड़ी मात्रा में आई। ये कह रहे हैं कि आप करोड़ों रुपए डिजिटल को promote करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब जो 'भीम' ऐप बनाया गया है, 'भीम' ऐप में एक नए पैसे का खर्च नहीं है। इससे बिना खर्च transaction हो रहा है। किसी बैंक को एक रुपए का कोई कमीशन नहीं जाता है। इसलिए दुनिया paper less, premises less banking की तरफ जा रही है, इसमें भारत के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हाँ, हो सकता है, हमारी व्यवस्थाएँ कम होंगी, तो साल-दो साल और ज्यादा लगेंगे, 5 साल और लगेंगे, लेकिन शुरू करना या यह दिशा गलत है, यह विचार मैं समझता हूँ कि उपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसको promote करने के लिए अपने-

अपने इलाके में भी लोगों को हमें समझाना चाहिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए।

अब देखिए, हमारे देश में रेलवे है। इसमें सामान्य मानव भी जाता है। आज रेलवे में 60 से 70 प्रतिशत booking online होने लगी है। उनकी पेमेंट online होती है और अगर वे टिकट cancel करते हैं, तो पैसा online वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं, जो शहरों में रहते हैं। अगर उनको बिजली का बिल भरना है, तो पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी, आज वह घर आकर रात को 12 बजे अपने मोबाइल फोन से बिजली के बिल की पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर यह सुविधा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है, तो अच्छी बात है। हाँ, हमें उसकी कमियों की चिन्ता जरूर करनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी में कोई कमी आती है, तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन यह कल्पना ही गलत है, अगर हम यह negativity लेकर चलेंगे, तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं।

रुपे कार्ड के बारे में अभी अरुण जी बता रहे थे। इस देश में जन-धन एकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रुपे कार्ड दिए गए हैं। आपको अंदाज नहीं है कि इसकी ताकत क्या होती है। आम तौर पर जेब में यह कार्ड होना एक वर्ग के लिए बड़ा prestigious हो गया है। पेमेंट करना है, तो कार्ड से करना है। यह भी हवा बन गई है कि यह गरीब का तो विषय ही नहीं है। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे कि वे बेंगलुरु से आ रहे थे, तो उनके साथ कोई IT Professional बैठे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर की एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि demonetization से उनका ड्राइवर

बहुत खुश है। उन्होंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बताया कि उसने कहा कि देखिए, आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूँ। वह उनको कार्ड दिखाने लगा। उसको बड़ा आनंद था। अब देखिए, इससे समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव की व्यवस्था आई है। इससे एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। जिसके घर में एक साइकिल भी नहीं आती है, वह खुशी से समा नहीं पाता है, जब उसके पास मोटरसाइकिल आ जाती है। जिसके पास स्कूटर हो, अगर वह छोटी सी कार लाता है, चाहे पुरानी भी लाता है, तो वह गर्व करता है। समाज के छोटे-छोटे लोगों के जो aspirations हैं, उन aspirations को पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।

अब Direct Benefit Transfer से कितना बड़ा फायदा हुआ है। मैंने उस सदन में विस्तार से इसके बारे में कहा है। Direct Benefit Transfer के द्वारा हम करीब-करीब 50 हजार करोड़ रुपए, जो कभी leak होते थे और हर वर्ष होते थे, अब तक बचा पाए और आगे पता नहीं, कितने बचा पाएँगे। Scholarship जैसी सुविधा में एक ही व्यक्ति छ: जगह पैसे लेता था। विधवा पेंशन, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वह विधवा भी हो गई और चेक भी कट रहा था। Direct Benefit Transfer Scheme के कारण ये जो leakages थे, जो बिचौलिए ले जाते थे, जिनसे देश का बहुत बड़ा खजाना लूटा जा रहा था, उन पर रोक लगी है।

(4जी/एससीएच पर जारी)

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : इसके कारण Direct Benefit Transfer Scheme का भी फायदा हुआ है, इसलिए हमें digital payments को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हम जितना प्रयास कर सकें, करते रहना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अपनी व्यवस्था को विकसित किया है। Posh machines की आवश्यकता को देखते हुए, बहुत तेज़ी से posh machines बढ़ाई जा रही हैं। Online payments को आगे बढ़ाने के लिए ई-वॉलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही Internet Banking को बढ़ावा देने की दिशा में काम चल रहा है।

इतनी तेजी से technology develop होगी, अब सिर्फ 'आधार' के आधार पर सब काम होंगे। उसके लिए mobiles की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हर व्यक्ति अपनी पेमेंट कर पाएगा, अब वे दिन दूर नहीं हैं। इन व्यवस्थाओं को या तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करें और इन स्कीम्स को व्यवहार में लाने का प्रयास करें।

'BHIM App' के माध्यम से भारत सरकार की छत्रछाया में एक बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनी है। हम BHIM App को पॉपुलर करेंगे। इससे किसी व्यापारी या बाहर की किसी एजेंसी को कोई लेना-देना नहीं होगा, यह एक सीधा-सीदा और enabled platform है, जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए।

अब देखिए, जो ड्राइवर्स हाईवेज़ पर जाते हैं, हम जानते हैं कि टोल पर देर तक रुकने के कारण पेट्रोल और डीज़ल का कितना व्यर्थ खर्चा होता है। 8 नवम्बर के बाद उस पर भी बल दिया गया है, ताकि टोल टैक्स देने के लिए ड्राइवर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और Radio-frequency Identification (RFID) के ज़रिए टोल-टैक्स दें। पहले इक्का-दुक्का लोगों के पास यह व्यवस्था थी। इतने कम समय में, अब करीब-

करीब 20% ट्रैफिक में RFID के द्वारा पेमेंट ली जाती है। कार आती है, सीधे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, टैक्स डिपॉज़िट हो जाता है और कार चली जाती है। अब उसको देर तक वहां रुकना नहीं पड़ता है। अगर यह काम और आगे बढ़ेगा, तो देश का कितना पेट्रोल बचेगा। इसी प्रकार आज पेट्रोल पम्पस पर करीब-करीब 29%-30% लोगों ने digital currency से काम करना शुरू कर दिया है। हमने चन्द्रबाबू नायडु जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट आई है। अब उस पर अध्ययन हो रहा है और जल्दी ही उसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। हम बदलाव के लिए तैयारी करें।

एक विषय है, banking system. इस पर अगर आप कुछ भी कहते हैं, तो उसके जवाब में मैं यह कहूंगा कि वह पुराने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने सबसे पहले छ: Debt Recovery Tribunals की रचना की और बैंकों में जो Debt बकाया है, उसके बारे में सरकार ने initiative लिया।

बैंकों में जो appointments होती थीं, उनके लिए कोई नियम नहीं था, यह काम एक घिसी-पिटी व्यवस्था के तहत ऐसे ही चल रहा था। इस सरकार ने एक Bank Board Bureau बनाया, जो independent agency है और अब वही बैंकों में रिक्रूटमेंट करती है। उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने इस दिशा में काम करके banking व्यवस्था में professionalism लाने का प्रयास किया है।

फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी वर्ल्ड, इन सबकी दो दिन की एक round table conference आयोजित की गई। उन्होंने विस्तार से इस विषय पर आत्ममंथन किया, चिंतन किया कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था को global level के

standard तक कैसे लाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी कमियों को समझा और उसको ठीक करने का प्रयास किया।

रिज़र्व बैंक की गरिमा के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मुझ पर हमला हो, हमारी पार्टी पर हमला हो, सरकार पर हमला हो, यह बहुत स्वाभाविक है, यह तो चलता रहेगा, लेकिन रिज़र्व बैंक या रिज़र्व बैंक के गवर्नर को इसमें घसीटने का कोई कारण नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मान-मर्यादा कायम रखने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। इनसे पहले जो गवर्नर थे, उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन मैंने उसका भी विरोध किया था कि यह शोभा नहीं देता है। ऐसी चीज़ों को विवादों से परे रखना चाहिए, बाकी सरकार की व्यवस्थाएं तो चलती ही रहेंगी। अर्थव्यवस्था चलाने में रिज़र्व बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी credibility की दिशा में हम लोगों का सक्रिय सकारात्मक योगदान होना चाहिए, लेकिन जो लोग सरकार पर आरोप लगाते हुए रिज़र्व बैंक की गरिमा पर भी आरोप लगाते हैं, मैं उनसे आज बड़े दु:ख के साथ एक बात कहना चाहता हूं। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने 2008 में एक किताब लिखी थी, 'Who Moved My Interest Rate'. उस किताब में उन्होंने लिखा था, "तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक Liquidity Management Committee को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज़ और परेशान था।..."

(4h/rpm पर जारी)

RPM-PK/4H/6.30

श्री नरेन्द्र मोदी: महोदय, उन्होंने लिखा है कि चिदम्बरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्र में ओवरस्टैप किया था। लिक्विडेट मैनेजमेंट पूरी तरह से रिज़र्व बैंक का फंक्शन है। इस विषय पर उन्होंने मुझ से परामर्श भी नहीं किया, बल्कि अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय, मेरे कार्य-काल के अंतिम वर्ष में, हम दोनों के बीच, असहज़ संबंध के लिए टोन सैट करेगा। रिज़र्व बैंक के एक्स-गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गम्भीर आरोप लगाया है और अपनी किताब में छापा है। अभी तक इसका किसी ने जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं, इसलिए कुछ कहेंगे, तो अलग बात है। यह बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा ये भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैं इस बात को मानूंगा कि इसे हम राजनीति से परे रखें और इस इंस्टीट्यूशन का गौरव बनाए रखने की दिशा में प्रयत्न करें।

सभापति जी, हमने क्या किया है, वह मैं बताना चाहता हूं। आरबीआई की ताकत बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट में संशोधन कर के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की है। कई वर्षों से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसे कोई नहीं कर रहा था। हमने इसकी स्थापना की। इस समिति को मॉनिटरी संचालन की पूरी स्वायत्तता दी गई है। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के दो अधिकारियों के अलावा तीन विशेष इसके सदस्य हैं। इस समिति में केन्द्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। मॉनिटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी स्वायत्तता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है,

लेकिन इस सरकार ने वह स्वायत्तता आरबीआई को दी है और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है।

महोदय, यह बात सही है कि कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो नहीं आती है। पहले भी जो सरकारें आई थीं, उन्होंने भी कुछ न कुछ तो करने का प्रयास किया होगा। हम यह तो नहीं कहते कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस बारे में तो मैं लाल किले से बोला हूं। मैंने लाल किले की प्राचीर से बोला, वह हिन्दुस्तान के किसी और प्रधान मंत्री ने नहीं बोला। मैंने कहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से जितनी भी सरकारें आईं, जितने भी प्रधान मंत्री आए, जितने लोगों ने काम किया है, उन सबका योगदान है, तब देश आज यहां पहुंचा है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारा नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। उनको पसंद नहीं है कि किसी ने कोई काम किया है, तो उसका उल्लेख तक करें। इतिहास गवाह है। यह बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया है। देखने में ये छोटे-छोटे निर्णय लगेंगे, लेकिन इन निर्णयों ने सामान्य मानवों की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है।

महोदय, पहले अफेडेविट को अटेस्ट करने की प्रथा थी। एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉरपोरेटर के घर लोग ठप्पा लगवाने के लिए आकर खड़े हो जाते थे, क्यू लग जाती थी। मैं देखता था कि कोई पियून बैठता या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था और वह ठप्पे मार देता था। हमने उसे समाप्त कर के सैल्फ-अटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी और उसके कारण वे उस संकट से बच गए, क्योंकि जब उसकी फाइनल अपॉइंटमेंट होगी, तो वह अपनी ओरिजनल कॉपी लेकर जाएगा। आज तो जेरॉक्स का जमाना है। इस सबको करने की क्या जरूरत है। नॉन-गैजेटेड पोस्ट के लिए हमने इंटरव्यू खत्म

कर दिए। अब टैक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा और जो उसकी मेरिट होगी, उसके आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। उसके कारण पहले जो करप्शन होता था, वह रुक गया है।

महोदय, हमने 1100 से अधिक कानूनों को खत्म किया है। इन्हीं दो सालों में खत्म किया है। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति के बारे में कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं कि पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही हैं। पुरानी प्रक्रिया और मेरा-तेरा, सब चला गया है और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टीकल भी लिखे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के द्वारा लीकेजेज़ को रोका गया है। पहले यदि कोई कंपनी रजिस्टर करनी होती थी, तो सात-सात दिन, 15-15 दिन और दो-दो महीने लगते थे। आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, यह व्यवस्था की है। पहले पासपोर्ट बनवाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज पासपोर्ट एक हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है। अब पोस्टल के जो हैड ऑफिसेस हैं, उन्हें भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसका भी लाभ सामान्य मानवों को मिलने वाला है और उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है।

(4 जे/पीएसवी पर आगे)

PSV-PB/4J/6.35

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत): हम यह भी जानते हैं कि कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय था। सरकार ने उसको आसानी से लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाया। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जिसकी चर्चा अभी काफी नहीं हुई है, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ। सरकार की खरीद करने की जो परम्परा होती है, उसमें हम लोगों ने GeM को लॉंच किया है- Government e-Marketplace. इस व्यवस्था

को वर्ल्ड बैंक के South Asia Procurement Innovation Award से भी सम्मानित किया गया है। अब उसमें दुनिया में जिसको भी सरकार को देना होगा, वे ऑनलाइन आते हैं, अपनी लिस्ट रखते हैं और सरकार उसमें से तय कर सकती है। आर्थिक लाभ भी हुआ है और यदि 5,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना हो तो इस GeM के माध्यम से कर सकते हैं। उस दिशा में हमने व्यवस्था की है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ गुड गवर्नेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से एक पारदर्शिता लाने की दिशा में हम बड़ी सफलता पाए हैं। इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक नयी योजनाएँ बनाई हैं। आप हर योजना में देखिए। 'उज्ज्वला योजना'- हम जानते हैं कि गैस के सिलेंडर का क्या जमाना था। एमपीज़ को 25-25 कूपंस मिला करते थे और उन 25 कूपंस को लेने के लिए लोग कतार लगाते थे, वे भी दिन थे। 2014 के चुनाव में 9 सिलेंडर दें या 12 सिलेंडर दें, उसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया था। इस सरकार की कार्यसंस्कृति में कितना फर्क है! गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा, ये सपने में कभी सोच नहीं सकती थीं, अब तक करीब-करीब 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसे 5 करोड़ परिवारों तक पहुँचाने का पूरा इरादा है। देश में 25 करोड़ गरीब परिवार हैं, उनमें से 5 करोड़ गरीब परिवारों को इसे पहुँचाने का प्रयास है। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' है। महिलाओं के नाम पर घरों के रजिस्ट्रेशन की कानूनन व्यवस्था की गई है। 'मनरेगा' में काम करने के लिए आज 55 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो पहले 40, 42 या 45 प्रतिशत हुआ करती थीं। 'मुद्रा योजना'- मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, without guarantee दिए जाते हैं। पैसे लेने में 70 प्रतिशत महिलाएँ

हैं। यानी entrepreneur के रूप में हमारे देश की महिलाएँ इसके साथ जुड़ रही हैं। 'पंडित दीनदयाल अन्त्योदय योजना'- Self Help Group के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलते थे, लेकिन पूरे भारत में और Eastern India में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। पूरे हिन्दुस्तान में गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपये प्रसूता में IMR-MMR के लिए, इस बात को लागू करने का काम हुआ है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को बहुत बड़ी मात्रा में स्वीकृति मिली है। वह एक सामाजिक आन्दोलन बना हुआ है। 'सुकन्या समृद्धि योजना'- बच्चियों के नाम पर एक करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और 11,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जो इनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। 'महिला शक्ति केन्द्र'- 500 करोड़ की लागत से 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में इसकी स्थापना हुई है।

'मिशन इंद्रधनुष'- बच्चों का टीकाकरण नहीं होता था। सरकार चलाती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे। 55 लाख बच्चे ऐसे ध्यान में आए, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। 'मिशन इंद्रधनुष' के कारण उन बच्चों को खोजा गया और उनकी जिन्दगी बचाने की दिशा में काम किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में-- यहाँ पर मैं हैरान था-- स्वच्छता का मजाक उड़ाया जा रहा था। क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम में से कोई नहीं है, जो गंदगी में रहना चाहता है। हम यह भी जानते हैं कि स्वच्छता behaviour का इश्यू ज्यादा है, infrastructure का तो उसके साथ आता है। मैं कहूँगा कि हम राजनेता कभी-कभी कम पड़ रहे हैं। मैं इस देश की मीडिया का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि स्वच्छता के आन्दोलन को उसने उठा दिया। आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए ईनाम

दिए जा रहे हैं, स्वच्छता के सम्बन्ध में आज हिन्दुस्तान भर में फंक्शंस आयोजित किए जा रहे हैं। वरना मीडिया सरकार के किसी भी कार्यक्रम की निगेटिव रिपोर्टिंग करे, वह बहुत स्वाभाविक है। यह कार्यक्रम एक ऐसा अपवाद है, जिसको सरकार से भी और राजनेताओं से भी दो कदम आगे मीडिया के लोग ले गए हैं और स्वच्छता को एक आन्दोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उनका अभिनन्दन करता हूँ।

(4के/वीएनके पर जारी)

VNK-SKC/4K/6.40

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : और यहां कोई खड़ा होकर कहता है कि टॉयलेट है, पानी नहीं है। महात्मा गांधी जी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते, तो क्या हम लोग यही भाषा बोलते? क्या यह हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक चीज कर ही नहीं सकते हैं? क्या हर चीज में हम विरोध करेंगे? मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में sanitation coverage, जो पहले 42 परसेंट था, इस आंदोलन के बाद वह 60 परसेंट पहुंचा है। हम जब भी टॉयलेट की बात करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं या शहर में भी झुग्गी-झोंपड़ी में जो महिलाएं रहती हैं, उनको कितनी पीड़ा होती थी, जब तक अंधेरा नहीं होता, तब तक वे शौचालय नहीं जा सकती थीं। हमें गर्व होना चाहिए, यह 'तू-तू, मैं-मैं' का विषय नहीं है, लेकिन जब इसको लेकर कोई मज़ाक उड़ाते हैं, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। यह मज़ाक का विषय नहीं हो सकता है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए Universalisation of Women Helpline 181, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया। 18 स्टेट्स एण्ड यूटीज़, इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33 परसेंट और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटीज़ के अंदर यह compulsory कर दिया गया है। हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है, जिसको हिन्दुस्तान में और लोग करें, मैंने सबके सामने इसका प्रेजेंटेशन किया है। उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है, जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है... एक पैनिक बटन की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर आने वाले हैं।

किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसके कारण.... अब सबसे बड़ी बात, 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना', हमें पसंद आए या न आए, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है, तो हमें उसको उसकी इन्कम के assurance के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वह डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर वह बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बरबाद होता है तो भी, अगर इंश्योरेंस मिलता है और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50 प्रतिशत किसानों का इंश्योरेंस का काम किया है और सरकार ने भी करीब-करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस 'फसल बीमा योजना' को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। इसमें पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ राज्य इसमें बहुत पीछे हैं, यह चिंता का विषय है। इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।

श्री नरेन्द्र मोदी : बाद में करते हैं, सर जी, एक बार हो जाए। आपको तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा, आप बैठिए न।

नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन, देखिए नीम कोटिंग, नीम कोटिंग के कारण दो महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, एक तो जमीन को फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वह केमिकल इंडस्ट्री में raw material के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे, वे भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100 परसेंट नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवाय उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है। इससे चोरी रुक गई है, आज यूरिया की ब्लेकमेलिंग नहीं हो रही है। यूरिया नहीं मिल रहा है, ऐसी किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही है। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वह आप देख सकते हैं।

हमारे देश में दाल का उत्पादन, पल्सेज़, इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया है और उसका परिणाम यह है कि आज करीब-करीब 50 से 60 प्रतिशत वृद्धि की संभावना इस बार पैदा हुई है। हमारे देश के किसानों ने सरकार के आह्वान को स्वीकार किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस काम को उन्होंने किया है।

e-NAM, electronic market, 500 मंडियों में, अब किसान जहां भी ज्यादा दाम पर माल बिक सकता है, वह इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेच सकता है। 500 मंडियों में मोबाइल फोन के द्वारा आज मेरा किसान अपना व्यापार कर सके, ऐसी स्थिति बनी

है। करीब 250 मंडियों ने इस काम को पूरा कर दिया है। राज्यों को कुछ कानून बदलने थे, कुछ राज्यों ने कानून बदले हैं, लेकिन हम फूड प्रोसेसिंग जानते हैं, हमारे किसान को लाभ तब होगा, जब हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देंगे।

(4एल/एनकेआर-एचके पर जारी)

NKR-HK/4L/6.45

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत): सरकार ने 100 परसेंट एफ.डी.आई. एलाउ की है ताकि फूड प्रोसेसिंग को मदद मिले और value addition हो, हमारे किसानों को ज्यादा इन्कम हो और उस दिशा में काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

आदिवासियों का सशक्तीकरण - करीब 28 विभाग का कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ संबंध रहता है। हमने पहली बार एक ट्राइबल सब-प्लान बनाकर राशि तो बढ़ा दी, लेकिन वनबंधु कल्याण योजना के तहत एक comprehensive plan बनाया, ताकि उसका outcome दिखाई दे। उस दिशा में काम करने का हमने सफल प्रयास किया है। Forest Rights Act को मजबूती से लागू करने की दिशा में हमने काम किया है और tribal areas में पहली बार, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मिनरल्स हैं, माइनिंग हैं, वे ज्यादातर tribal बैल्ट में हैं, चाहे कोयला हो, आयरन हो या कुछ और हो, लेकिन वहां उन्हें लाभ नहीं मिलता था। पहली बार सरकार ने District Mineral Foundation बनाया और वहां खदानों से जो कुछ निकलता है, उस पर टैक्स लगाया। मुझे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनके 7 जिले ऐसे हैं, वहां जो खनिज निकलता है, हमारे District Mineral Foundation बनाने के कारण, उन जिलों के विकास के लिए, उन्हें अब extra budget की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी

मात्रा में राशि उन गरीब आदिवासियों के काम आने वाली है, जिसका हमने इंतजाम किया है। हमने जो Rurban Mission चलाया है, उसका सबसे बड़ा लाभ आदिवासी क्षेत्रों में होने की संभावना है। आदिवासी इलाके में बड़ा Marketing place develop होना चाहिए। यदि Marketing place develop होता है तो वहां एजुकेशन सिस्टम आता है, medical facilities आती हैं, दूसरी entertainment की सुविधाएं, मार्केट की सुविधाएं आदि आती हैं। धीरे-धीरे अगल-बगल के पचासों गांवों और पूरे इलाके का वह केन्द्र बन जाता है। Rurban के द्वारा tribal belt में 300 ऐसे नए शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और यह आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ..(व्यवधान)..

इसी प्रकार, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, स्वच्छता देश में एक जन-आन्दोलन बनना चाहिए और जन-आन्दोलन बनाने की दिशा में हम सबका कोई-न-कोई योगदान होना चाहिए। जब से हमने स्वच्छता के लिए independent agencies के द्वारा प्रचार करना शुरू किया है, उससे शहरों के बीच में स्पर्धा शुरू हुई है। एक शहर अगर आगे गया, तो दूसरा शहर उस शहर से कम्पीट करने लगता है कि देखो, वह शहर तो आगे चला गया, हम क्यों सफाई नहीं कर रहे हैं? धीरे-धीरे यह सोच नीचे तक जाने लगी है। हम लोगों को इस पर बल देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जितनी political parties हैं, सभी political parties को कहीं-न-कहीं सरकार चलाने का इन दिनों अवसर मिला है, कोई नगर पालिका में होंगे, कोई जिला पंचायत में होंगे, कोई राज्य में होंगे। अपनी पार्टी की सरकारों में जहां आपको सेवा करने का अवसर मिला है, आप उनमें भी तो competition चलाइए। Communist-ruled जितने शहर हैं, उनके बीच

स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा कीजिए, Communist-ruled जितनी District Panchayats हैं, उनके बीच स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा कीजिए। इससे एक वातावरण बनेगा। बी.जे.पी. ruled जितनी स्टेट्स होंगी, वहां की नगर पालिकाएं कम्पीटीशन करें। एक बार ऐसे कम्पीटीशन को हम आगे बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा स्वच्छता अभियान सफल होगा। यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह जन-आन्दोलन बनना चाहिए। यह युग की आवश्यकता है, behavioral change की आवश्यकता है। हम जानते हैं और World Bank का record कहता है कि अस्वच्छता के कारण, हैल्थ सुविधाएं देने के कारण हमारे ऊपर करीब ढाई लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। अगर हम केयर करें तो देश की इतनी बड़ी राशि बचा सकते हैं। यह World Bank का रिकॉर्ड है, हिन्दुस्तान के संबंध में। एक गरीब आदमी पर एक साल में करीब 7000 रुपया खर्च आता है और गंदगी से बीमारियां आना बहुत स्वाभाविक है। हम इसे बचा सकते हैं।

बच्चों को हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, इसे हर कोई मानता है, लेकिन जब हम ऐसा कहें तो कोई कहेगा कि वहां पानी नहीं है, वहां नल नहीं है, वहां यह नहीं है, वह नहीं है। बच्चा किसी कुएं पर जाएगा तो कहेंगे कि ऐसे हाथ नहीं धोते हैं। यह जो सोच है, इसी सोच ने देश को यहीं दबोच कर रखा हुआ है। आप कुछ सोचें तो सही, कुछ निकले तो सही। कठिनाइयां आयेंगी तो रास्ते भी निकलेंगे लेकिन हम घर में बैठकर अपने बच्चों को समझाने की बजाए कहें कि वहां यह नहीं है, वह नहीं है - ऐसे देश बदलता नहीं है। ऐसी मानसिकता से हम देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इस मानसिकता से हमें बाहर आना चाहिए।

(4M/DS द्वारा जारी)

KSK-DS/6.50/4M

श्री नरेन्द्र मोदी (क्रमागत) : दुनिया में हम अपने पड़ोस के देशों को देखें। चाहे हम साउथ कोरिया को देखें, मलेशिया को देखें, थाइलैंड को देखें या सिंगापुर को देखें, वे छोटे-छोटे देश हैं, उन्होंने स्वच्छता के लिए 15-15 साल लगा दिए और आज वे हम लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में नज़र आते हैं। हम हिन्दुस्तान में वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा भी तो सपना होना चाहिए कि अगर छोटे-छोटे देश इसमें सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है, जिस प्रकार का वातावरण बना है, किसी शायर ने कहा है-

"शहर तुम्हारा, क़ातिल तुम, शाही तुम, हाकिम तुम,
मुझे यकीन है कि मेरा ही कसूर निकलेगा।"

लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें से हम ज़रा बाहर आएँ।

मैं एक और विषय कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। "एक भारत, श्रेष्ठ भारत", इस काम को हमने 31 अक्तूबर को सरदार पटेल की जयंती पर लाँच किया है। हमारे देश में दुनिया के किसी राज्य के साथ सिस्टर स्टेट बनना, सिस्टर सिटी बनना, यह तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमारी अपने ही देश के अलग-अलग लोगों से मिलने की आदत नहीं बनी। हमने इस प्रकार से कर दिया, जिसके कारण कई राज्यों को लगने लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है। हमें अपने देश के पोटेंशियल को पकड़ना चाहिए। हमने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम के तहत

इसके लिए कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि इस सदन में जो लोग हैं, वे इसको समझने में और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे, दो राज्यों के बीच में एमओयू करते हैं। अभी 12 राज्यों ने शायद एक-दूसरे के साथ यह कर लिया है, जैसे हरियाणा और तेलंगाना ने किया है। हरियाणा में तेलुगु भाषा के 100 सेंटेंसेज़ हरियाणा के लोग बोलना सीखें, जैसे- हॉस्पिटल कहाँ है, रिक्शा कहाँ मिलेगा, होटल कहाँ है, बस स्टेशन कहाँ हैं, पुलिस थाना कहाँ है आदि। यह उनको सीखने को मिलेगा और तेलंगाना के लोग हरियाणा की भाषा सीखें। हरियाणा में कभी तेलंगाना का फिल्म फेस्टिवल हो, कभी हरियाणा का फिल्म फेस्टिवल तेलंगाना में हो। उनके बीच क्विज़ कॉम्पिटीशन हो। तेलंगाना की क्विज़ कॉम्पिटीशन में हरियाणा के बच्चे हिस्सा लें और तेलंगाना के बच्चे हरियाणा की क्विज़ स्पर्धा में भाग लें। इस प्रकार, यह एक प्रकार से देश को जानने का और देश से जुड़ने का अभियान है और इसको हम जितना बढ़ाएँगे, उतना ही अच्छा होगा। कभी-कभी किसी चीज़ के लिए हिन्दी भाषा में शब्द भी नहीं होते, लेकिन तमिल में उसके लिए अच्छा शब्द होता है, लेकिन उससे हम परिचित नहीं हैं। मराठी में बढ़िया शब्द होता है, बांग्ला में बहुत बढ़िया शब्द होता है, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं। हमारे देश की जो इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को जोड़ने की दिशा में "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का एक अभियान चलाने की दिशा में प्रयास चल रहा है।

सभी आदरणीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, उनके प्रति मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इसको समर्थन देने के लिए अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को अपना

समर्थन देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

(समाप्त)

श्री सभापति : शरद जी, आप कुछ कहने वाले थे। ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please allow us. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please allow us. We listened to the Prime Minister for 90 minutes. ...(Interruptions)...

श्री सभापति : शरद जी, आप कुछ कह रहे थे? ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : सर, मैं यह कह रहा था कि जब किसानों की बाबत प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे ...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We listened to the Prime Minister for 90 minutes without disruption. Please give us 90 seconds. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please, sit down. ...(Interruptions)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, normally, in the Motion of Thanks discussion on the President's Address, this kind of a discussion doesn't take place. It takes place in this House in the debates.

MR. CHAIRMAN: Because the hon. Prime Minister had mentioned that he could intervene after he completes. ...(Interruptions)...

श्री शरद यादव : अरुण जी, उस समय आप नहीं थे। ...(व्यवधान)... सभापति जी, ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कोई क्लैरिफिकेशन की परम्परा नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, when our names are taken, when our parties are referred to, when our politics is referred to, we have this opportunity to explain. ...(Interruptions)... This cannot be denied. That is our democratic right.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, even then राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कोई क्लैरिफिकेशन की परम्परा नहीं है। ...(व्यवधान)...

(4एन/जीएसपी-एमसीएम पर आगे)

GSP-MCM/4N/6.55

SHRI SITARAM YECHURY: This is wrong because we have this right. Whenever there is a reference made to any particular name or any particular party, that person or that party representative gets the chance to clarify. ...(Interruptions)... That is why, when we were asked not to interrupt, we did not. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I shall now take up... ...(Interruptions)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : ये तो हर विषय पर बोलते हैं।....(व्यवधान)....

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, every time, they are doing ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: It was said, later, they will clarify. The Prime Minister said… …(Interruptions)… This is now that 'later'. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: We will follow the convention of the House. …(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: With all respect to the hon. Prime Minister following the true principles of Parliamentary democracy, we did not stand up once. We heard him uninterrupted because… …(Interruptions)… No, Sir, one minute. …(Interruptions)… Sir, the Prime Minister was telling the people of the country to take the credit card and eat the credit card for lunch. …(Interruptions)… दाल, रोटी, चावल नहीं खाएगा तो प्लास्टिक खाएगा क्या?….(व्यवधान)….

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, please do not allow this now. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: No, no. That is enough. …(Interruptions)… That is enough. …(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we did not interrupt… …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Hon. gentlemen, please. …(Interruptions)… Please sit down. …(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we want… …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you had allowed, you means the Chair… …(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: It was said, Sir. …(Interruptions)… Otherwise, it is… …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: The Chair had allowed… …(Interruptions)… The Prime Minister will reply to the debate on the Motion of Thanks. There is no reply. …(Interruptions)… It is only a monologue delivered as an election campaign. …(Interruptions)…

SHRI ANANTHKUMAR: Hon. Chairman, Sir, please do not… …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: He has replied. …(Interruptions)… He has replied to the debate. …(Interruptions)… I want to hear the Minister of Parliamentary Affairs. …(Interruptions)..

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Chairman, Sir, let the Motion of Thanks on the President's Address be commended to the House. …(Interruptions)… Let it be put to vote of the House. …(Interruptions)… This should not be allowed.

MR. CHAIRMAN: I think, that is enough. I shall now take up the Amendments which have been moved. …(Interruptions)..

SHRI SITARAM YECHURY: We want to seek clarifications, Sir. …(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I am sorry. …(Interruptions)..

SHRI SITARAM YECHURY: You cannot do this and be discriminatory. …(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I am not discriminating. …(Interruptions).. Please be careful. …(Interruptions).. Please be careful. …(Interruptions)..

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, this has never happened. …(Interruptions)… This is not the precedent. It has never happened. …(Interruptions)… He cannot say this to the Chair. He is casting aspersions on the Chair. …(Interruptions)… Sitaram Yechury is a senior Member and what he is doing is something wrong. …(Interruptions)… What he is saying is wrong. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: I had asked the.. …(Interruptions)…

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, he is casting aspersions on the Chair. …(Interruptions)…

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, Sitaram Yechury ji cannot impute motive on the Chair. …(Interruptions)… Your ruling is final. …(Interruptions)…You have already started it now. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: One minute. …(Interruptions)… One minute, please. …(Interruptions)…

श्री शरद यादव : सभापति महोदय,….(व्यवधान)….

MR. CHAIRMAN: Sharad ji, one minute. …(Interruptions)… I have watched with much distress what has happened this afternoon in the House. I am not putting blame on anybody because if you look at it in totality, all the Members of the House have to share the blame in some measure or the other. I think, the normal practice, to my understanding, has been that when a speaker has the floor and somebody wishes to intervene, the person speaking concedes. Now, that has happened very often. That is a known practice. Today, different people wanted to intervene somewhere. The hon. speaker, at that moment of time, did not concede. Now, the practice is, if it is not conceded, it is not conceded. You can draw conclusions as to why it was not conceded, whether it was in keeping with parliamentary etiquette, etc. etc.

SHRI DEREK O' BRIEN: That is what we are trying to say. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: No, but your …(Interruptions)…

SHRI DEREK O' BRIEN: That is what precisely we are trying to say. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: I am sorry. …(Interruptions)… No, no. I am sorry. …(Interruptions)… It is an established practice. The debate has been conducted. Everybody has spoken. Reply has been given. Now, at the end of the reply, there is no further discussion. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is an established practice of the House that the reply should be given. …(Interruptions)… This is not a reply. Leave that point aside. …(Interruptions)… This is not a reply. …(Interruptions)… It is an established practice of the House… …(Interruptions)…

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, he cannot decide the nature of the reply. …(Interruptions)…

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, the reply is not to satisfy him. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is an established practice of the House …(Interruptions)… If somebody's name is taken, if my name is taken, the established practice is that he is given the right to respond. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Well, the established practice has not been observed today. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you have upheld the practice all through. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Yes, I have. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, if my name has been taken, I have a right to respond. …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: All I have to say, Mr. Yechury, is that the established practice of hearing you has not been conceded. …(Interruptions)…

(Contd. by SK/4O)